न्यूज़ पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया

NEWSPAPERS ASSOCIATION OF INDIA

Volume XVIII वर्ष 18 | No. 10 अंक: 10 | Sep.-2013 सितम्बर–2013 | Rs. 5/- per copy

डेढ़ अरब की कब्रगाह यानी दिल्ली की तिहाड़ जेल

संजीव चौहान

डेढ़ अरब का वार्षिक बजट। पांच–पांच सुरक्षा एजेंसियां। आसमान छूती चार दीवारी। हर इलाके पर 24 घंटे क्लोज सर्किट कैमरों की नजर। जगह–जगह मेटल डिटेक्टर। हर कोने पर निगरानी टॉवर। हर जेल में तीन–तीन भीमकाय दरवाजे। मोबाइल फोन के सिग्नल जाम करने के लिए अनगिनत जैमर। देखने–सुनने में कहीं कोई कोर–कसर बाकी नजर नहीं आती है। इसके बाद भी दक्षिण–एशिया की सबसे मजबूत समझी जाने वाली तिहाड़ जेल का कैदी इतने सुरक्षा इंतजामों के बीच भी असुरक्षित है। आखिर क्यों?

ऐसा नहीं है कि, राम सिंह की संदिग्ध मौत के बाद ही इस तरह का सवाल जन–मानस के जेहन में कौंधा है। तिहाड़ में जब–जब किसी कैदी की मौत हुई। तब–तब तिहाड़ सुर्खियों में आई है। अब राम सिंह ने फांसी लगाई, तो फिर तिहाड़ जेल के सुरक्षा इंतजाम को लेकर देश में कोहराम मच गया। देश के गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को बयान देना पड़ा। तिहाड़ जेल में बंद राम सिंह कोई आम–कैदी नहीं था।

दिसंबर 2012 में राम सिंह की करतूत ने सरकार की चूलें हिला दीं थी। राम सिंह की मौत हत्या थी या आत्महत्या? इन सवालों के जबाब आने वाले समय में खोजे जाते रहेंगे। कुछ सवालों के जबाब मिल जायेंगे। तमाम सवाल फाइलों में दफन कर दिये जायेंगे। ऐसा नहीं है, कि तिहाड़ जेल में ही कैदी या कैदियों की मौत होती है। देश के बाकी हिस्सों में मौजूद जेलों में भी कैदी मरते हैं। यह दूसरी बात है कि, देश के दूर–दराज की जेलों में मरने वाले कैदियों की मौत की खबरें दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती हैं।

उदाहरण के लिए जनवरी 2013 में कपूरथला मॉडर्न (पंजाब) जेल में बंद जालंधर निवासी अनिल पुत्र कर्मचंद की संदिग्ध मौत। जेल प्रशासन के मुताबिक अनिल की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अनिल के परिजनों के मुताबिक हादसे से कुछ दिन पहले, जब वे अनिल से मिले, तो वह ठीक था।

अक्टूबर 2012 में पंजाब की गुरदासपुर जिला जेल में राज कुमार की संदिग्ध मौत हो गयी। जेल प्रशासन के अनुसार तबियत खराब होने पर राज कुमार को अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गयी। राजकुमार की मां जीतो के मुताबिक बेटे की मौत से चार पांच दिन पहले, जब वह बेटे से जेल में मिली, तब राजकुमार सही था। जुलाई 2012 में हैदराबाद की चेरापल्ली जेल में कैदी ने साथी कैदी को कैंची घोंप दी। हमलावर कैदी का नाम नरसिम्हम था। हमले में 60साल के एक कैदी की मौत हो गयी। पांच कैदी जख्मी हो गये। सवाल ये पैदा होता है कि, हमलावर कैदी के पास जेल के अंदर कैंची पहुंची कैसे?

छत्तीसगढ़ राज्य की जेलों में 2011–2012 और 2012 से 2013 में अब तक तीन कैदी मर चुके हैं। तीनों की मौत का कारण उनका एचआईवी (एड्स) से पीड़ित होना बताया गया। इसके अलावा राज्य की अन्य जेलों में 102 और कैदी बीमारी के चलते मर गये। जेलों में हुई मौतों के इन आंकड़ों की पुष्टि राज्य के गृहमंत्री ननकू राम कंवर भी करते हैं।

वर्ष 2009 के आंकड़े बताते हैं कि, अकेले मध्य–प्रदेश की जेलों में नवबंर 2009 तक 66 कैदियों की मौत हुई थी। हांलांकि ये मौतें बीमारी से होने की बात कही गयी थी। इस हिसाब से राज्य की जेलों में औसतन हर पांचवें दिन एक कैदी की मौत हुई। इसी अवधि में राज्य में उज्जैन और इंदौर की जेल में 7–7 कैदियों की मौत हुई। यही वजह थी कि राज्य में जेल में कैदियों की मौत के मामले में यह दोनों ही जेल अव्वल रहीं।

वर्ष 2010 में देश में करीब एक हजार चार सौ (1400) कैदियों की जेलों के अंदर मौत हो गयी। इस बात की तस्दीक भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी करता है, कि जेलों में होने वाली मौतों में 70 फीसदी मौत टीबी (क्षय रोग) से होती हैं। कैदियों की मौत के लिए अधिकांशतरू जेल प्रशासन ही जिम्मेदार होता है। कद्धैदी चाहे बीमारी से मरे, या कैदी की हत्या हो या फिर उसे आत्महत्या का मौका मिल जाये। जेल प्रशासन किसी भी तरह की मौत में खुद को नहीं बचा सकता है।

इसका मजबूत उदाहरण है वर्ष 2000 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई 68 साल के सतनाम शाह की संदिग्ध मौत। सतनाम भारतीय वायुसेना का रिटायर्ड विंग कमांडर था। मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में सतनाम शाह, बेटी के साथ तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी के रुप में बंद था। सतनाम शाह की तिहाड़ में हुई संदिग्ध मौत की जांच राजौरी गार्डन के तत्कालीन एसडीएम विवेक खन्ना से कराई गयी। जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया, कि 25 नवबंर 2000को हालत ज्यादा खराब होने पर सतनाम को डीडीयू अस्पताल से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में दाखिल कराया गया। इससे पहले तक जेल प्रशासन सतनाम को जेल परिसर में मौजूद अस्पताल में ही दाखिल किये रहा। जबकि सतनाम शाह ने कई महीने पहले ही तिहाड़ जेल प्रशासन को बताया था, कि उसे खाने में परेशानी हो रही है। एक महीने के अंदर ही सतनाम का वजन भी 10 किलोग्राम घट गया। जेल के डाक्टर फिर भी सतनाम शाह को एंटी–बायटिक दवाईयों पर चलाते रहे। 20 सितंबर 2000 को हालत ज्यादा खराब होने पर सतनाम को दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में दाखिल कराया गया। जीबी पंत के डाक्टरों ने बायोप्सी–इंडोस्कोपी के बाद बताया, कि शाह को कैंसर जैसी कोई बीमारी नहीं है। अंतत 6 दिसंबर 2000 को लंबी बीमारी के बाद एम्स में दाखिल सतनाम शाह की मौत हो गयी।

सतनाम शाह की मौत की जांच कर रहे एसडीएम को एम्स के डाक्टरों ने बताया कि सतनाम को कैंसर की बीमारी थी। जब सतनाम को जीबी पंत से एम्स में दाखिल किया गया, तो वो 'सैप्टीसीमिया' से भी ग्रसित हो चुका था। एम्स के डाक्टरों ने एसडीएम को बताया, कि सतनाम शाह की आंतो और पेट में सूजन थी। इन तमाम तथ्यों की पुष्टि सतनाश शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हुई। इन तमाम सनसनीखेज खुलासों के सामने आने पर एसडीएमध्जांच–अधिकारी ने तिहाड़ जेल और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की थी।

यहां सवाल यह पैदा होता है, कि जिस तिहाड़ जेल का मौजूदा वक्त में सालाना बजट करीब डेढ़ अरब (140,93,85000–00) रुपये है। इस बजट का 42 फीसदी कैदियों की सुरक्षा पर, 22 फीसदी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, 12 फीसदी खान–पान पर खर्च होता है, तो फिर कैसे जेल के भीतर सतनाम शाह और बिस्किट किंग राजन पिल्लई जैसे कैदी मर जाते हैं, इलाज के अभाव में। कैसे और क्यों लगा लेते हैं, राम सिंह जैसे खतरनाक कैदी फांसी? इतने चाक–चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच में।

इन तमाम सवालों के मुद्दे पर कश्मीर घाटी सहित देश की तमाम जेलों में लंबे समय से कैदियों के हित में काम करने वाली अंजलि कौल 'अदा' कहती हैं– " जेलों की और वहां बंद कैदी की सुरक्षा के लिए मोटे बजट रख देने से कुछ नहीं होगा। जरुरत है इस भारी–भरकम बजट को, सही तरीके से सही समय पर सही जगह मतलब, कैदियों के हित में इस्तेमाल करने की। जेलों में जानवरों की तरह ठूंस–ठूंस कर कैदियों को भरे जाने की बजाये, जेल की सामर्थ्य के हिसाब से वहां कैदियों को रखा जाये।" अंजलि के मुताबिक भारत की करीब 1393 जेलों में 3 लाख 68 हजार कैदी जानवरों की मानिंद भरे हुए हैं। प्रत्येक कैदी पर सरकार औसतन 19 हजार 446 रुपये 50 पैसा सालाना खर्च करती है। यानि देश भर की जेलों में बंद कैदियों के ऊपर करीब 715 करोड़ 61 लाख 28 हजार रुपये सालाना का खर्च। इसके बाद भी राम सिंह जैसे खतरनाक कैदियों की तिहाड़ जैसी अति–सुरक्षित जेल में 'संदिग्ध' हालातों में मौत हो जाती है।

अंजलि कौल के मुताबिक– 'इसका जबाब सिर्फ और सिर्फ उस जेल प्रशासन से ही मांगा जाना चाहिए, जिस जेल में राम सिंह जैसे खतरनाक कैदी , जो सिर्फ सजा के हकदार हैं, मगर वे संदिग्ध हालात में मरे हुए मिलते हैं।' अंजलि कौल के कथन की कहीं–न–कहीं देश का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी पुष्टि करता है। आयोग की 2004–2005 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक– 'जिन जेलों में 2 लाख 37 हजार 617 कैदी ही रखने की क्षमता है। उन जेलों में 3 लाख 36 हजार 151 कैदी भरे हुए हैं। कैदियों की यह संख्या जेलों की निर्धारित क्षमता से 41 फीसदी ज्यादा है।' बकौल अंजलि कौल–'ऐसे में भला कैदी बीमारियों से ग्रसित होकर कैसे नहीं मरेंगे। कैसे दमघोंटू जिंदगी से आजिज आकर सुसाइड करने पर नहीं उतरेंगे कद्धैदी। कैदी हैं तो क्या हुआ? आखिर हैं तो इंसान ही। लेकिन जेलों की उस भीड़ में, जहां इंसान और जानवर की भीड़ के बीच का अंतर ही खतम हो जाता हो। इंसान आखिर कैसे खुद को जिंदा रखेगा?'

1990 के दशक में बिस्किट किंग और उद्योगपति राजन पिल्लई की तिहाड़ में हुई संदिग्ध मौत की जांच के लिए सरकार ने जस्टिस लीला सेठ आयोग गठित किया था। लीला सेठ आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था, कि तिहाड़ जेल में कैदियों के समुचित इलाज, रहन–सहन का कोई इंतजाम नहीं है। जस्टिस लीला सेठ आयोग की सिफारिश थी, कि तिहाड़ जेल में जानवरों की तरह कैदियों को ठूंस–ठूंस कर रखे जाने की वजह से भी, उनकी उचित देख–रेख नहीं हो पाती है। इसका इंतजाम अगर होता, तो शायद राजन पिल्लई को सही समय पर उचित इलाज देकर बचाया जा सकता था। राजन पिल्लई की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि राजन पिल्लई की पत्नी को इस मामले में मुआवजा दिया जाये।

जस्टिस लीला सेठ आयोग ने तिहाड़ जेल को लेकर यह कड़वा सच 1990 के दशक में उजागर किया था। इसके कई साल बाद भी जस्टिस लीला सेठ आयोग की सिफारिशों को अमल में नहीं लाया गया। इसकी पुष्टि करती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कुछ साल पहले आयी, वो रिपोर्ट जिसमें आयोग ने भी माना है, कि भारतीय जेलों में क्षमता से कई गुना ज्यादा कद्धैदी जेलों में ठूंस–ठूंस कर रखे गये हैं।

आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक क्षमता से अधिक कैदी रखे जाने के मामले में, देश की राजधानी दिल्ली में स्थित दक्षिण एशिया की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली तिहाड़ जेल अव्वल नंबर पर है। तिहाड़ में क्षमता से 224 फीसदी ज्यादा कद्धैदी रखे गये हैं। दिल्ली के बाद देश के जिन सूबों का नंबर क्षमता से ज्यादा कैदी जेलों में रखने में आता है, उनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर–प्रदेश का नंबर आता है। वहीं दूसरी ओर आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू–कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, उत्तराखंड, दमन और दीऊ, दादर और नगर हवेली तथा लक्षदीप की जेलें ऐसी भी हैं, जिनमें क्षमता के मुताबिक ही कैदी बंद करके रखे गये हैं।

BRUTALS IN THE SHACKLES OF COPS

Bomb blast at Ahmedabad, Mumbai and Hyderabad in 2013! Surat mourned with deadly blasts! Bomb created fear at Chinna Swamyy stadium Bangalore before the IPL match! Yes, these are the black events, those spoilt the sleep of Indian intelligence bureau and the Karnataka and other states' cops once in the last five years. Especially, the severe bomb blast that took place at the generator room of Chinna Swamy stadium at the capital city Bangalore became an international issue, as it happened before an IPL cricket match between Royal Challengers Bangalore and Mumbai Indians, which was consisted of a number of celebrity international cricket players. The atrocious event was happened on April 17 2010 in which 6 police were injured. The Karnataka cops severely doubted on the Bhatkal brothers, who were indulged in such vicious activities so far. The master mind has been detained by the Indian intelligence and national security force! Yes, the master minds of a number of blasts Yaseen Bhatkal and Asatulla aftar are finally arrested at the border of India and Nepal in Bihar state on the basis of the information given by a suspicious terrorist Abdul karim tunda. The two terrorist brothers were so vile and were accused in a number of cases wanted by multi state police forces.

These criminal terrorists troubled the entire country for a long time. A bomb blast happened at Surat and Ahmedabad swallowed 60 people. Another deadly bomb blast was occurred at Mumbai on July 13th 2013 in which 22people were killed and more than 130 people were injured. Another major city Pune of Maharashtra also witnessed a black evening during the protest against corruption in accordance with the support for anti-corruption activist Anna Hajare was going on. The blast was mild, but also created a number of injuries. The bomb which was kept in polithin bag injured an activist named Lakshmi Narayan, who was a staunch supporter of the protest.

Nailing the Indian Mujahideen (IM) and its operatives for continuously plotting terror operations in the country, the National Investigation Agency (NIA) had on July 17 filed its first chargesheet in court laying bare the outfit's modest origins in 2003 to present pan-Indian penetration.

Though, the IM's top leaders — Iqbal Bhatkal, Riyaz Bhatkal, Yasin Bhatkal, Asadullah Akhtar Haddi, Ariz Khan and Tehseen Akhtar were not named in the chargesheet, their roles in the growth of the outfit were mentioned, said sources. Of the five terror operatives charged by the NIA, two were from Bihar — Mohammad Danish Ansari alias Waheb (Darbhanga) and Mohammad Aftab Alam al. Hours after top Indian Mujahideen leader Mohammed Ahmed Zarar Siddibapa aka Yasin Bhatkal's arrest, his family said they ... The operation to arrest Indian Mujahideen chief Yasin Bhatkal was so secret that even after his arrest, only few top Bihar Police officers were informed and they too were not told about where he was being held for questioning, an officer said. Bihar Police played a major role in the arrest of Yasin Bhatkal, who is wanted in bomb blasts across the country, Bihar Police chief Abhayanand said in Patna on Thursday. "It was Bihar Police that mainly helped NIA (National Investigation Agency) and other government agencies to arrest Bhatkal," Abhyanand told mediapersons. "A team of Bihar Police officials have interrogated Bhatkal at a secret place after he was arrested," he said. East Champaran district superintendent of police Vinay Kumar said that Bhatkal would be brought to Motihari from Raxaul under tight security before being taken to Delhi. According to a senior officer at the Police Headquarters, the entire operation to arrest Bhatkal was kept a close secret till the last moment. "A few selected police officers were aware of the special operation to arrest Bhatkal," the officer said. An additional director general of police rank officer told IANS on condition of anonymity that even after Bhatkal was arrested, only few top officers were informed and they were also not told about where he was kept for interrogation. "It was a very sensitive case, so information was not shared with others except those involved in this operation," he said. The state government has sounded an alert across Bihar, particularly in the border districts following Bhatkal's arrest. "We have alerted district police officials and asked them to keep a close watch...," an official of the state home department said. The terrorists were operating with intelligence in each blast however left a clue during the Hyderabad bomb blast happened on February 21st 2013 in which 16 innocent people were killed and more than 100 populace were injured. But, a CC camera captured the terrorist's picture, who was riding a bicycle, which was used for the installation of bombs in the spot. This event completely changed the investigation direction of the National Security Force, who is now succeeded in arresting these deadly terrorists. Mr. The central home minister Sushil Kumar Sindhe has also confirmed to the media that, the terrorists were already been arrested a day before its declaration in the Indo-Nepal border but was kept under secrecy for maintaining confidentiality of the case.

The Bangalore city police commissioner Mr. Raghavendra Auradkar has also stated that, the city police are already in consistent touch with the national intelligence bureau and will take these terrorists into their custody soon after the judicial proceedings, as these terrorists are needed for the state in two major cases. Cutting across party lines, politicians welcomed the arrest of Indian Mujahideen founder Yasin Bhatkal from the Indo-Nepal border on Thursday morning. Terming the arrest as a big achievement for the intelligence agencies, political leaders said that Bhatkal's arrest will help control terrorism. Minister of state for home RPN Singh said Indian Mujahideen co-founder Yasin Bhatkal, who was apprehended yesterday, was a bigger terrorist than Lashkar-e-Taiba operative Abdul Karim Tunda, arrested by Delhi Police recently. "The government is committed to continue its fight against terror. We will not take rest till all such terrorists are not put behind bars," he told reporters here. Singh said the UPA government has assured the country that it would pursue all the people who waged. "I take this opportunity to once again congratulate central agencies after we arrested Tunda and again we have apprehended a bigger terrorist. I once again reiterate our commitment to fight against terrorists. I hope there will be no politics as far as terror is concerned," he said. Bhatkal, Indian Mujahideen co-founder and one of India's most wanted terrorists, was arrested from the Indo-Nepal border in north Bihar after being on the run for over five years. Both the big catches by Indian security agencies have taken place close to the Indo-Nepal border, fanning speculations that the Himalayan nation played a crucial part in apprehending the wanted terrorists. Like Tunda, who was shown as arrested from the Indo-Nepal border earlier this month, Indian authorities said that Bhatkal was arrested along the border on Thursday and not on Nepali soil. "Bhatkal was arrested on the Indo-Nepal border and we can confirm that he was not nabbed in Nepal," said Indian Embassy spokesperson Abhay Kumar. Nepal Police officials claimed ignorance of the arrest. "Reports about his arrest in Nepal are false. We haven't arrested him nor handed him over to Indian authorities," said Nepal Police spokesperson Nabaraj Silwal. It is worth mentioning that both in Tunda and Bhatkal's cases, initial reports about their arrests mentioned they were caught in Nepal. Though both countries deny it, Tunda was reportedly arrested by Nepali police in Kathmandu and handed over to their Indian counterparts a day later at the Banbasa-Mahendranagar border. Such secret arrests of Indian terrorists and insurgents in Nepal and quiet handover at the border is nothing new and there is a pattern to it due to lack of a new extradition treaty between both neighbours. The treaty, which New Delhi wants signed at the earliest, has been in the pipeline since 2005 but Nepal has been backtracking citing political instability and transition in the Himalayan nation. Despite the absence of the treaty both countries have been handing over criminals and terrorists across the border without anything on record to show they were arrested in another country. In 2010, Anthony Shing aka Ningkhan Shimray, the foreign affairs chief of the Nationalist Socialist Council of Nagaland (Issac-Muivah) was arrested at the Tribhuwan International Airport here. Shing was apparently on his way from Bangkok to New Delhi to take part in peace talks with the Indian government when he 'disappeared'. Earlier in July the same year, another rebel leader from the north-east, Niranjan Hojai, the 'commander-in-chief' of the Dima Halam Daogah (Jewel) group of Assam, was also arrested in Nepal and handed over to Indian authorities. Officially, however, he arrest was shown from a place in Bihar along the international border. India's porous border with Nepal allows many Indian terrorists and criminals to enter the country undetected and hide. In June, notorious Bihar criminal Bablu Dubey was arrested in Kathmandu and later handed over to India. Kashmiri terrorists have also used the Nepal route to enter India from Pakistan to avail the state government's rehabilitation package. Since 2010, nearly 300 former militants have returned to their home state. However, it is not only an Indo-Nepal practice. India has also successfully managed to get hold of many rebels of the north-east who were hiding in Bangladesh. Till Delhi signed an extradition treaty with Dhaka in January this year, several top militant leaders – including Ulfa chairman Arabinda Rajkhowa and NDFB commander-in-chief Ranjan Daimary – were arrested in Bangladesh and "pushed back" to India, an euphemism used by both countries to hide the actual place of capture. In the cases of both Nepal and Bangladesh, the system has worked well for India. The National security force is going to produce these deadly terrorists in front of the court for undertaking further investigating steps. However, the country's security forces are succeeded in incarcerating two illicit terrorists and have proved their workmanship. But, as a known fact, terrorism has become a continuous process in troubling the nations. One dead terrorist is creating a number of such illicit criminals, who are disturbing the world peace. This arrest has increased in proving the power of Indian security force and also has increased the weight of responsibility on the shoulders of Indian security forces and the government.

Nomination Open For National Achievement Award of the Newspapers Association of India (NAI)

Newspapers Association of India (NAI) which represents the press at the grassroots level in almost all languages and territories of the country, and which constitutes the core of the press community in this country since its inception in 1993, has endeavored to bring the Small and Medium newspapers and media organization from the length and breadth of our great country together under the ambit of one platform . Until now we were successful in bringing together approximately 7500 such entities as active members under our umbrella. These newspapers are published in Hindi, English and other vernacular languages. Together they enjoy a reach to every nook and corner of the country. Our association actively takes up matters relating to the difficulties being faced by the publishers of these newspapers and also disseminates information useful to them from time to time. The Conference would be focusing on the role that the regional newspapers play in the strengthening of this World's largest democracy. The emphasis would be on how the regional newspapers strengthen our democratic institutions with adherence to secular credentials. The strength of our democracy lies in the dissemination of information and these regional and vernacular language newspapers with their reach deep in the hinterland can and plays an effective role in the propagation of democratic ideas and advantages of people power.

The Special Award is - Dr. M.R Gaur Lifetime Struggle & Achievement Award

In Electronic Media

Best News Channel
Best News Anchor
Best Crime Reporter
Best Reporter
Best Cameraman
Best Editor
Best Show

In Print Media

Best News Agency
Best Magazine
Best Regional Newspaper (Daily , Weekly , Monthly , Fortnightly)
Best Editor
Best Reporter
Best Colum Writer
Best Photographer

Other Categories

Best NAI State Committee
Best RTI Activist
Best Documentary For rural Development
Best Radio Station
Best Radio Jockey
Best Social Worker
Best Social NGO
Best IPS Officer
Best IAS Officer

Good News for all Publisher

In this Occasion we are going to Publish Small and medium Newspapers Information Directory with all details of the newspapers and magazine please Send you details of Newspapers

Name of Newspaper
Language
Year of Establishment
Periodicity
Circulation
Size of Publication
Editor
Publisher
Phone No./ Mob. No.
Address
Email- Id
State of Publication

Also You can publish
6 cm ×11 cm Adv. In just Rupee 250/- INR
This offer is only for News papers/ Magazine Publisher
Mail us your details at
nai.newsmedia@gmail.com &
naiawards2013@gmail.com

News Papers Association of India Achievement Award-2013 and 21th Annul Conference

In the field of Journalism & Social Activities NAI Awards 2013, submissions open

The News Papers Association of India invites journalists from developing India and the Pacific to submit published articles written, News, Videos, Photos, Social Activities, Agriculture or Rural Documenters' in January – 2012 to till date in connection with the 2013 annual Developing NAI Journalism Awards . If you are interested in participating in the 2013 NAI Award program, so please Send Your Port Folio (Profile).In C.D also You Can mail your details at: - naiawards2013@gmail.com , nai.newsmedia@gmail.com

Statement of Terms and Conditions

Articles , News , Videos , Photos , Social Activities , Agriculture or Rural Documenters must be published And Telecast works and may have appeared in a regional newspaper, magazine, news wire service or website between 1st January 2012 to 30th September 2013.

The judges shall not be bound to award a prize in any categories where they do not feel that the quality of entries merits it. The awardees are selected through an extensive selection process. Jury members will independently inspect each entry and rate them based on their respective

Judging criteria. Those entries that do not fulfill the criteria shall be disqualified. NAI Awards shall not be liable to give any explanation to anyone for disqualification of entries.

Submission deadline for NAI Awards 2013 is 30th September 2013, 6 pm Indian time

Contact to

News Papers Association of India
A/115 4th floor Vakil Chamber, Shakarpur
Vikas Marg , Delhi - 110092
011- 22058133 , 9971847045
Visit as:- naiindia.com
e-mail :- gs@naiindia.com

Suryabhan Singh Rajput
President (Editor – Nand Darshan Daily)
Mob- +91 9923199115
E-mail:- nanddarshandaily@gmail.com

Vipin Gaur
General Secretary (Editor In Chief – The Indian Majesty)
Mob.9810226962, 9718919456
E-mail :- nai.newsmedia@gmail.com

सम्पादकीय

बहादुर जाबाज बोलने से काम नहीं चलेगा

देश मे बढ़ते जा रहे है अत्याचार कानून का खोफ ही नहीं है मुजरिमों को क्या यही हो रहा है भारत निर्माण, क्या यही है भारतीय सभ्यता, क्या यही वो भारत है जो देवी देवताओं का देश है, शर्मशार होती जा रही है मर्यादा रोजाना महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी देश मे एक बड़ी घटना हुई जब देश एक साथ था और ये तब हुआ था जब एक लड़की के साथ कई लोगों ने दरिंदगी की जिसे निर्भया नाम दिया गया जिस हादसे ने भारत को दुनिया के सामने एक ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया जहाँ से सभी देश भारत को गन्दी नजर से देख रहे थे पूरे भारत की जनता सडको पे उतर आई थी और सरकार से सवाल कर रही थी, की क्या सुरक्षा है भारत मे महिलाओं की ,कैसी सुरक्षा है भारत मे महिलाओं की, क्या कर रहा है कानून पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था सत्ता मे बेठे सभी लोग यही कह रहे थे की कानून को मजबूत किया जाएगा, ऐसे हादसे अब नहीं होंगे, देश मे महिलाओं की सुरक्षा बढाई जाएगी। हाल ही की एक घटना ने फिर से भारत वासिओं के दिल को देहला दिया जब मुंबई मे फिर से एक ऐसी घटना हुई जिसमे एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और वो लड़की भारतीय लोकतंत्र के चोथे स्थाम्ब का हिस्सा है वो लड़की पत्रकार है पत्रकार जो समाज का आइना है जो समाज मे होने वाली सभी घटनाओं को जनता के सामने सत्ता के सामने लाने का काम करते है जो देश मे जागरूकता फेलाते है और हर आम इन्सान के साथ जमीनी सतह से जुड़े है आज लोकतंत्र के एक हिस्से के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार कोन है शायद प्रशाशन देश की सत्ता देश का कानून और हम खुद भी जिम्मेदार है क्योंकि हर बार जब भी जनता सड़कों पे उतरती है तो सरकार अपने झूठे वादों से बहला फुसला कर हमे शांत कर देती है और हम खुद भी भूल जाते है, जब कोई नया हादसा होता है तो फिर सड़कों पे उतर जाते है शायद इसकी आदत हमे भी और सरकार को भी हो गई है और इसका फाएद सरकार उठा रही है आज सरकार व खुद मीडिया ने उसे जाबाज और बहादुर बना दिया, क्या पहले वो लड़की बहादुर नहीं थी, पहले जाबाज नहीं थी जो की इस घटना के बाद उसके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए उसे बहादुर जाबाज पत्रकार लड़की बना दिया। देश मे पत्रकारिता छेत्र मे हजारों महिलाए काम कर रही है जो अपराध , राजनीती , सामाजिक समस्यों की खबरों के लिए सभी मे सुधर के लिए रात दिन सड़कों मे, गलियों दूर दर्ज इलाकों मे निडर होके जाती है पर जिस प्रकार की घटनाए देश मे रोजाना सुनने को मिल रही है उससे लगता है की आज सभी महिला पत्रकारों के दिल मे डर पैदा हो गया होगा उनके दिल मे भी सवाल होगा की एक पत्रकार के साथ मुंबई जैसे शहर मे ऐसा हादसा होता है तो और दुसरे छेत्रों मे भी ऐसी वारदातें हो सकती है कैसे करेंगी वो अपनी पत्रकारिता जहाँ कुछ भी हो सकता है महिला पत्रकारों के साथ कोई सुरक्षा नाम की चीज ही नहीं है। अगर देश मे किसी भी नेता , या प्रशाशन के किसी भी अधिकारी के साथ कोई हादसा हो जाए तो वोह लोकतंत्र पे हमला, लोकतंत्र का अपमान पर उसी लोकतंत्र के चोथे स्थंभ के हिस्से के साथ ऐसी दर्दनाक घटना हो जाती है तो उसे बहादुर, जाबांज कह कर सहानुभूति दी जाती है झूठा आश्वासन दिया जाता है मीडिया भी उनकी बाते उन्ही के तरीके से दिखता है कभी कभी तो ऐसा लगता है की सरकार कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसे हादसों से और हमेशा मोका मिल जाता है की कब किसको जाबांज बोले बहादुर बोले, जब ऐसे हादसे होते है तो सरकार का जवाब होता है, सरकार जांच कर रही है, हमे बहुत दुःख है की इस प्रकार की घटना हुई , सोनिया गाँधी व कई नेताओ ने घटना की कड़ी निंदा की, मुख्या मंत्री जी ने पीडिता के इलाज के लिए इतना –– देने का ऐलान किया , घटनाओ को रोकने के लिए एक विशेष बैठक बेठी , महिला सुरक्षा के लिए सरकार बनाएगी नए कानून पर ऐसा होता क्यों नहीं है। जब से निर्भया के साथ हादसा हुआ तब से रोजाना ऐसे हादसों की खबरे बढती जा रही है इसका कारण शायद खुद हमारी सरकार है, प्रशाशन है, जो मुजरिमों को जुर्म करने के लिए रोक नहीं पा रही है और किसी के दिल मे डर नाम की चीज हे नहीं है प्रशाशन का, जुर्म करने वाले बेखोफ है और आम आदमी को जुर्म सहना पड़ रहा है भारत मे महिलाओं को देवी , गंगा बोला जाता है पर सबसे जादा अत्याचार भारत मे लड़किओं के साथ ही हो रहे है सिर्फ भारत ही नहीं विशव भर से भारत मे पर्यटन के लिए जब महिला भारत आने की सोचती है तो उसे कई बार ये सोचना पड़ता है की वो सुरक्षित रहेंगी या नहीं क्यूंकि भारत मे पहले भी कई विदेशी महिला पर्यटकों के साथ बलात्कार जैसे मामले हो चुके है और भारत मे दुष्कर्मी दुष्करम करने से चुक नहीं रहे है। अगर हमारा प्रशासन चाहे तो हम सुरक्षित हो सकते है सभी महिलाओं को आजादी मिल सकती है अत्याचारों से, पर तब जब सभी राजनैतिक दल एक दूसरे की टांग खींचना बंद करे और सच मे जनता की सुरक्षा के बारे मे सोचे नहीं तो जो हो रहा है वो रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है चाहे जनता सड़कों पे उतरे चाहे धरना करे हड़ताल करे क्योंकी जब भी कोई हादसा होगा तो कुछ न कुछ बहाने और झूटे वादे करके सब को घर भेज दिया जाएगा और इंतजार किया जाएगा किसी नये हादसे का और फिर कहा जाएगा हो रहा भारत निर्माण।

❑ विपिन गौड़

कौन तय करेगा भाजपा का भविष्य?

❑ दिलीप कुमार

जबसे विश्व हिन्दू परिषद् ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में चोरासी कोसी यात्रा का ऐलान किया तबसे राजनीतिक पंडितों ने इसमें तरह तरह के मुद्दे तलाशने शुरू कर दिए हैं। विश्व हिन्दू परिषद् के संरक्षक माननीय अशोक सिंघल जी के साथ प्रमुख संतों के एक शिष्ट मंडल ने यात्रा प्रारम्भ करने की घोषित तिथि से लगभग एक सप्ताह पूर्व श्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव से भेंट करके यात्रा के विषय में बताया और श्री मुलायम सिंह यादव से अयोध्या में राम मंदिर के मामले का वार्ता अथवा कानून बनाकर हल निकालने का अनुरोध किया। भेंट के बाद शिष्ट मंडल द्वारा बताया गया कि श्री मुलायम सिंह जी ने सहयोग का आश्वासन दिया।भेंट की फोटो जो जारी कि गयीं उनमे कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि श्री यादव या मुख्य मंत्री ने यात्रा का विरोध किया हो।लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्री आजम खान द्वारा इस भेंट पर आपत्ति जताने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार का रुख बदल गया।और उ.प्र सरकार ने यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया।इसके बाद जो कुछ हुआ वह सबको ज्ञात ही है।

अब हमारे राजनीतिक विश्लेषकों को एक नया विषय मिल गया है कि यह यात्रा हिन्दू वोटों को भाजपा के पक्ष में गोलबंद करने के उद्देश्य से आयोजित की गयी है। मेरा मत है कि अगर इस यात्रा का उद्देश्य हिन्दू वोटों का धुर्विकरण ही था तो भी क्या संविधान में अथवा किसी कानून में ऐसा करना प्रतिबंधित है? संविधान की प्रस्तावना में सबको "। न्याय,आर्थिक,सामाजिक और राजनीतिक " अधिकार दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 19 में सबको संगठन करने, विश्वास और आस्था की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। और किसी धार्मिक संगठन के लोगों को भी इससे वंचित नहीं किया गया है। अतः उ.प्र सरकार का यात्रा को प्रतिबंधित करने का निर्णय विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध में मा।इलाहाबाद उ।न्या। द्वारा प्रतिबन्ध को उचित ठहराते समय संविधान के उक्त प्राविधानों पर विचार किया गया है अथवा नहीं ये ज्ञात नहीं है।

जहाँ तक राजनीतिक विश्लेषकों का प्रश्न है अनेक विद्वानों ने ये मत व्यक्त किया है कि यात्रा से उ.प्र में मतदाता हिन्दू और मुस्लिम के रूप में धुरविकृत हो जायेंगे। जिसका लाभ भाजपा और सपा को मिलेगा और कांग्रेस व बसपा को नुकसान होगा।इनका कहना है कि धुर्विकरण न होने की स्थिति में मुस्लिम वोट सपा, बसपा और कांग्रेस में विभाजित हो जायेगा और हिन्दू वोट जातियों के आधार पर वोटिंग करेगा। जिसका नुकसान भाजपा को होगा। कुछ विश्लेषकों का मत है कि अब मुस्लिम मतदाता रणनीतिक रूप से मतदान करेगा और मुसलमान उसी को वोट देगा जो भाजपा को हरा सकने में सक्षम दिखाई पड़ेगा।

मेरे विचार में जहाँ तक मुसलमानों का प्रश्न है वो प्रारंभ से ही रणनीतिक रूप से वोट करता रहा है। पहले वो जनसंघ के विरोध में वोट करता था अब भाजपा के विरोध में मतदान करता है।हालांकि गुजरात में कुछ स्थानों पर मुसलमानों ने भाजपा के पक्ष में भी वोट किया और एक नगर पालिका में तो 43 में से 32 स्थानों पर भाजपा विजयी हुई जिनमे 27 सदस्य मुस्लिम थे।लेकिन गुजरात के आधार पर उ.प्र का आंकलन नहीं किया जा सकता है। जबकि भाजपा के प्रधान मंत्री पद के प्रमुख दावेदार श्री नरेन्द्र मोदी जी ने मुसलमानों को भी भाजपा से जोड़ने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया है। जिसकी मुस्लिम तबकों में भी अच्छी प्रतिक्रिया हुई है।लेकिन उ.प्र विचित्र है।यहाँ तो गुजरात से आये दारुल उलूम, देवबंद के प्रमुख बुस्तान्वी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्यूंकि उन्होंने गुजरात की आज की स्थिति को देखने और वहां मुसलमानों की प्रगति के बारे में बयान दे दिया था। दरअसल,हमारे सारे प्रगतिशील विश्लेषक भाजपा के प्रति एक हीनता ग्रंथि से ग्रस्त हैं।वो मुस्लिम मतदाताओं के मतदान व्यव्हार की चिंता करते हैं लेकिन हिन्दुओं के व्यवहार में आ रहे बदलाव को नहीं देखते हैं।आम तौर पर हिन्दू अलग अलग जातियों में बनता रहता है। और जातियां अलग अलग दलों में बंटी हैं।लेकिन जब हिन्दू अस्मिता का प्रश्न खड़ा होता है तो हिन्दू फिर जातियों से ऊपर उठकर हिन्दू के रूप में मतदान करता है।राम जन्मभूमि आन्दोलन के दौरान जातिवादी राजनीती को गहरा धक्का लगा था और लोग जातियों से ऊपर उठकर हिन्दू के रूप में संगठित हुए थे। लेकिन 1993 के बाद लगातार मीडिया द्वारा हिन्दू विरोध ी प्रचार के कारण और तत्काल कोई आसन्न संकट न दिखाई पड़ने के कारण हिन्दुओं ने पिछले कई चुनावों में अलग अलग जातियों के रूप में व्यवहार किया है। हालांकि 1998 और 1999 में लोकसभा के चुनावों में उ.प्र के मतदाताओं ने भाजपा को अच्छी संख्या में सीटें दिलायीं। लेकिन 2007 और 2012 के चुनावों में मुसलमानों द्वारा रणनीतिक मतदान के कारण ही क्रमशः बसपा और सपा पूर्ण बहुमत से जीतती रही हैं।

पिछले एक सवा साल के दौरान सपा की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े मिलाकर लगभग सौ से अधि ाक स्थानों पर सांप्रदायिक उपद्रव अथवा तनाव हुआ है।इनसे हिन्दू मतदाता आंदोलित हुआ है।इसके अतिरिक्त सपा सरकार ने अनेकों ऐसे कदम उठाये हैं जिनका सीधा लाभ केवल मुसलमानों को ही मिला है। जैसे कन्या धन योजना, दसवीं पास करने वाली मुस्लिम कन्याओं को तीस हजार रुपये दिया जाना, कब्रिस्तानों के लिए धन और जमीनें दिया जाना आदि। अब मुसलमानों के लिए सभी योजनाओं में 20 प्रतिशत आरक्षण की भी घोषणा की गयी है।अब हिन्दू समाज में इनकी प्रतिक्रिया तो होगी ही। इन सब कारणों से हिन्दू स्वतः ही गोलबंद हो रहा है।और ऐसे में चोरासी कोसी यात्रा ने भी अगर योगदान किया हो तो किसी को आपत्ति क्यों हो? अगर मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में करके राजनीतिक लाभ के लिए काम किया जाना जायज है तो यात्रा निकालकर हिन्दू मतदातों को गोलबंद करना नाजायज क्यों माना जाता है?

राजनीतिक विश्लेषक हमेशा हिन्दुओं के विभाजित रहने के लिए ही प्रयास रत रहते है। और इसके लिए जातिवाद के विष को बढ़ाने और फैलाने से भी परहेज नहीं करते। ऐसा क्यों है की जो समाज को जातियों और उपजातियों में बाँटने का काम करें वो तो धर्मनिरपेक्ष माने जाएँ और जो जाति विहीन समरस संगठित हिन्दू समाज के लिए कार्य करें उन्हें सांप्रदायिक माना जाये। असल में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक इन शब्दों को अपने अपने तरीके से सुविधानुसार इस्तेमाल किया जा सके इसीलिए पिछले पचास सालों में इन शब्दों की कोई विधिक परिभाषा नहीं बनायीं गयी जबकि इस बारे में अनेकों बार राष्ट्रिय एकता परिषद् और अन्य मंचों से मांग होती रही है। किस प्रकार मीडिया हिन्दुओं को बांटने का काम करता है इसका एक उदाहरण दिया जाना सामयिक होगा। 1977 में इमरजेंसी के विरुद्ध संघर्ष करके जनता पार्टी सत्ता में आई थी।इसमें तत्कालीन जनसंघ, लोकदल,संगठन कांग्रेस और कांग्रेस से अलग हुए धड़े सी घ्फ डी (जगजीवन राम, हेमवतीनंदन बहुगुणा, नंदिनी सत्पथी, के आर गणेश आदि) को विघटित करके शामिल किया गया था। सबसे बड़ा घटक जनसंघ था जिसके 98–99 सांसद चुनकर आये थे। ऐसा माना जाता था की जनसंघ और लोकदल घटक में अंदरूनी समझ बन चुकी थी और चौधरी चरण सिंह जनसंघ से ताल मेल कर रहे थे।ऐसे में सरकार बनने और दल का गठन होने के छह माह बाद ही विश्लेषकों ने इसके विरोध में टीकाएँ लिखनी शुरू करदी थीं। सितम्बर 1977 में उस समय की प्रमुख राजनीतिक साप्ताहिक पत्रिका रविवार में एक लेख छपा था जिसमे ये बताया गया था की चौधरी चरण सिंह जी के लोकदल और जनसंघ के बीच आपसी समझ के लिए कोई मिलन बिंदु ही नहीं है क्योंकि लोकदल की ताकत जातियों में विभक्त हिन्दू समाज में निहित है जबकि जनसंघ की ताकत जाति विहीन संगठित हिन्दू समाज में है।और आगे चल कर इस संगठित हिन्दू समाज की ताकत से घबडाये नेताओं ने एक विदेशी ताकत के इशारे पर दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाकर जनता पार्टी को विघटन के कगार पर पहुंचा दिया और तीन वर्ष से भी कम समय में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का ये प्रयोग असफल हो गया और इंदिरा गाँधी पुनः सत्ता में वापिस आ गयीं। आज भी हमारे मेकालेवादी और वामपंथी सोच से प्रभावित विश्लेषक हिन्दू समाज को जातियों से ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अब ये सम्पूर्ण हिन्दू समाज के लिए एक चुनौती है की वो जातियों और उपजातियों के रूप में विभक्त रहकर अपनी शक्ति और सामर्थ्य को तिरोहित होते देखना चाहते हैं या एक संगठित, सशक्त जाति विहीन समाज के रूप में अपने अस्तित्व का भान कराना चाहते हैं।ये स्मरण रखें की पिछले डेढ़ सौ सालों में जितने भी सुधारवादी आन्दोलन हुए हैं उन सभी ने जाति प्रथा और छोटे बड़े के भेद को ही हमारी सबसे बड़ी समस्या और बुराई बताया है।

THE POLICE SOVEREIGN HONOURED WITH AWARDS OF ITH HIS ACHIEVEMENTS

❑ *Pramesh Jain*

Trembling among the criminals! Break for illicit activities! Consciousness awakener for the cops! Kind for good and nightmare for the bad! Yes! It is none other than Mr. Jyothi Prakash Mirji, the most successful police commissioner of the capital city Bangalore, Karnataka. It was May 2nd 2011, the Karnataka state government implemented an order of in taking a dynamic officer as the captain of Bangalore city police and effected a change at the helm of city police by appointing Beladamadu Gangadhar Jyothi prakash Mirji as Bangalore police commissioner. Mr. Mirji on that occasion took over from Shankar M Bidari, who was made the additional director-general of police (railways), a post left vacant by Mirji.

Addressing presspersons after taking over, Mr. Mirji said that he would continue the precedent set by his predecessor and strive to uphold law and order. In what appeared to be a softening of the stand on the city's night life, Mr. Mirji said: "We will not be rigid. We will take the people's view into account. Elderly people have a certain view on the subject whereas the youth has a different view. He talked of taking it all into consideration before coming to a conclusion."

Soon after assuming the office of the city police commissioner, Mirji uttered that he wanted the force to work round-the-clock to ensure peace and tranquility, and also meet the expectations of the citizens. The commissioner fulfilled his assurance by working with utmost consistency, brilliance and intelligence for 24/7 throughout his profession in the garden city.

B.G. Joy Prakash Mirji was a 1982 batch Indian Police Service officer attached to the Karnataka cadre, took over as 26 {+t} {+h} Police Commissioner of the city. Mr. Mirji's career was with lots of ups and downs. He was Additional Director-General of Police (Railways) swapped before being appointed to the silicon city. The super cop shot into the limelight during

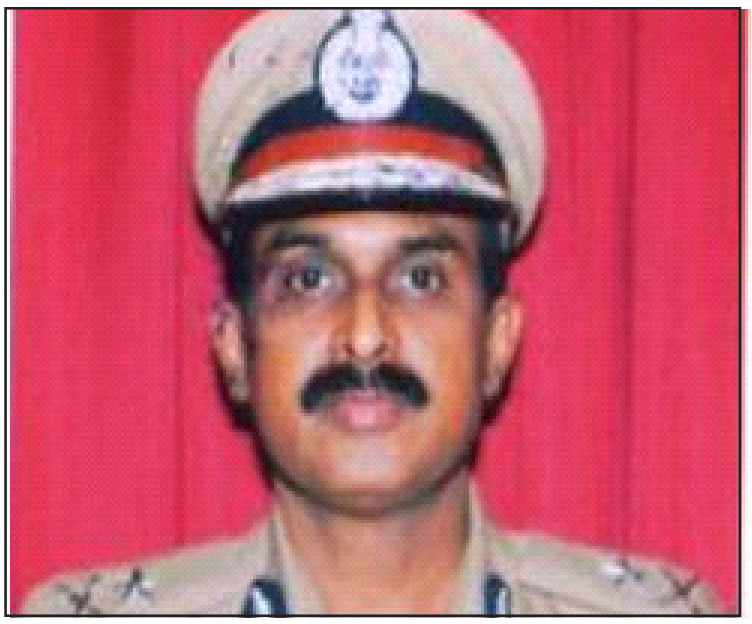

his stint with the Special Task Force, which was formed to nab forest brigand Veerappan. He, however, is credited with planning "operation cocoon", which resulted in the death of Veerappan in October 2004. He has also been decorated twice with the President's Police Medal.

The skipper was previously the chief of state police intelligence for two years before he was transferred as the ADGP (railways). His transfer from intelligence had then raised many an eyebrow since it was carried out when the then ruling BJP was facing dissidence from within its ranks.

The cop's utmost working efficiency was proved, when Indian Police Service officer from Karnataka, Mirji had headed the special task force (STF) constituted to track down the dreaded forest brigand, KM Veerappan. A year after he joined the STF, the Tamil Nadu police gunned down the criminal at Dharmapuri on October 18, 2004. He was awarded the president's Vishisht Seva Medal in 2008.

However, the professional way of Mr. Mirji was not so easier as a flower bed. The political context presided over the officer. New protector for the garden city! An unexpected change of a dynamic personality! Elections gave aid for mal administration! Yes, this is the doubt that knocked the hearts of entire bangaloreians on the calm evening of Thursday. The strict and stubborn officer Mr. Jyothi Prakash Mirji the commissioner of police of the city was transferred. It was the day on which the disciplined officer ordered for the arrest of 56 rowdy shelters, which was well performed by the city crime branch by the end of the day with his able guidance. The government ordered Mr. Raghavendra Auradkar to replace Mr. Mirji and even fixed the time for taking the charge at 7 o clock in the evening.

The charge taking was not on time! The rumor of politics was further proved when the new commissioner did not take the charge at said time. More interestingly the officer waited till the cm could confirm the orders. Even the central government and leaders were involved in the lobby that was proved with the statement of the chief election commissioner.

The central chief election commissioner acted as the propagandist! The appointed commissioner advocated in favour of the transferred and fixed a dead line for the charge taking as the next morning at 10.30 and their plan was finally successful. Once the home secretary for 2 years in the same city who worked for the well being of a particular section was crowned with the new controlling post.

The crisis emerged as a stage for political power struggle! The major political parties BJP and congress have been using this issue as a mean for their canvassing. But the most vulnerable thing is that the new commissioner belongs to the troop of batch no. 87 who is junior than 12 eminent and able officers, who are naturally questioning the authorities. Moreover, the administrative act strictly prohibits the transfer of officers from place to place almost before 2 years of retirement. Mr. Mirji had only 6 months for the ending of his career during that transfer, and the transfer proved a clear cut violation of the law.

The courageous officer was so confident about the regulations, who pleaded for justice against the violation of transfer policy and went for an appeal at high court. In the petition, Mr. Mirji has given a detailed analysis about his brilliant colourful career by questioning the authorities and their partiality regarding his transfer. The ex commissioner has proved his professionalism by quoting his brilliant and fair performance of his duty at Chikkamagalore constituency during the period of 1977 elections, when the constituency was highly sensational, as the then prime minister Mrs. Indira Gandi competed against the ex chief minister Mr. Veerendra Patil, which was ably organized by Mr. Mirji as the district superintendent. He was even summoned by the state government of Karnataka during the mid 90s during the controversy of Idaho field at Hubli and Mr. Mirji himself solved the crisis.

The petition also threw a bird view over the promptness of Mr. Mirji as an uncompromising crime investigator at Karwar, who successfully arrested an underworld don in the murder case of the congress party leader Vasanth Asnodikar. He was the officer who worked as the deputy commander of the police group during the forest combing operation against elephant killer Veerappan. His petition also led a way for the issue of notice to the election commission and the state government and also recrowned him to the city commissioner post. However fruit has been finally bored for all his sincerity, hard work and loyalty. The brilliant police officer Mr. Mirji has now crowned with the international award of "best police commissioner", as a new feather to his crown. United Nations advisor founder is Steve Chalke. And has presented this award to commissioner of police and joint commissioner of police and this is organized by Anitha, who is responsible for this event. Apart from his professional career, Mirji had earned his master's degree in business administration (MBA) from an Australian university.

Known to be an efficient administrator, Mirji has been friendly and transparent in functioning. He seldom blew his own trumpet, which perhaps explains the absence of his several professional achievements in his biodata. a police officer close to Mirji quoted him as saying quite often "My work is an open book; let others judge it,", which depicts the simplicity and human being inside Mr. Mirji out of his proficient regid profession.

राजदीप सरदेसाई और आशुतोष गुप्ता नौकरी छोड़ दें....सबसे मोटी पगार इन्हीं की है

मीडिया में इन दिनों एक मीडिया हाउस पब्लिक और मीडिया के बीच श्मारा–मारी का मीडिया बना हुआ है। नाम है टीवी–18 और इसका अड्डा है. .नोएडा फिल्म सिटी में। इस परिवार के दो भाई हैं। नाम है– सीएनएन और आईबीएन–7....सीएनएन का उस्ताद कोई राजदीप सरदेसाई और आईबीएन–7 का आशुतोष गुप्ता नाम का प्राणी बताया जाता है। गाहे–बगाहे दोनो की ही गिनती भारतीय मीडिया मठाधीशों में भी होती है। काबिलियत की वजह से नहीं, मीडिया, राजघरानों और सत्ता की गलियों में इनकी जुगाड़ के चलते। इनके अधीन दोनो ही चौनल किसी वरिष्ठ पत्रकार के हों ऐसा भी नहीं है। दोनो के दोनो ही भारत के धंधेबाज (व्यवसायिक) घरानों की नौकरी करते हैं। बदले में मोटी पगार (लाखों) लेते हैं। हांलांकि कि ऐसा नहीं है, कि यही बिचारे मोटी पगार ले रहे हों। इनकी तरह मीडिया को और भी तमाम बिचारे हैं, जो मोटी पगार पर बंधुआ मजदूरी करते हैं। मतलब मालिक (चौनल फाइनेंसर) जो कहेगा, वो करना इनकी मजबूरी है। वरना मालिक इनसे कह देगा...भागो चौनल से अगर हमारी मजदूरी करना तुम्हें नहीं जरुरी है।

खैर छोड़िये। इन दोनो के मालिकों ने इन्हें इस कदर हड़का दिया है इन दिनों...कि इन्हें नौकरी के लाले पड़े हैं। सो इन्होंने जल्दबाजी में अपनी पगार–परिवार सलामत रखने के लिए एक ऐसा जहर–बुझा नुस्खा खोजा है, जिसे अमल में आते ही....सैकड़ों परिवार चौराहे पर खड़े हो गये हैं। दोनो उस्तादों ने अपनी पगार और परिवार की सलामती का वास्ता देकर, कल तक इन्हीं के वफादार रहे, अनगिनत वफादारों और उनके परिवारों को इन्होंने दांव पर लगा दिया है।

मतलब अपनी पगार की खातिर दोनो उस्तादों ने अपने से नीचे वालों को, जिनकी पगार ((तन–खा) एक लाख से ऊपर है, उनकी नौकरी चबाना शुरु कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे हाथी मुंह में गन्ना चबाता है। वजह सिर्फ वही कि चौनल घाटे में है। खर्चे बढ़ गये हैं। मुनाफा तेल हो चुका है। मालिक का डंडा इनके सिर की तरफ घूमा। सो अपना सिर बचाकर इन्होंने अपने नीचे वालों के सिर मालिक के डंडे के नीचे दे पटके। बिलकुल वैसे ही जैसे अचानक सामने आये सांप को इंसान मार डालने के लिए एकजुट होकर टूट पड़ते हैं।

परमप्रिय कथित रुप से मेरे आदरणीय इन दोनो ही मीडिया के कथित मठाधीशों ने यह तक विचार करना मुनासिब नहीं समझा, कि अपनी पगार पचाने–बचाने के लिए आज जिस तरह और जिनके सिर यह कलम कर रहे हैं, उन्हीं की दम पर सीएनएन में राजदीप सरदेसाई राजदीप बन सके और आईबीएन–7 में परम आदरणीय आशुतोष गुप्ता आज डंके की चोट पर खुद को आशुतोष कह पा रहे हैं। जिनके आज यह दोनो अपने पेट–परिवार की खातिर सिर कलम करके बलि ले रहे हैं या ले चुके हैं, अगर दोनो चौनलों के शुरुआती दौर में, वे ही लोग इनके सिर कलम कर चुके होते, तो आज जो यह दोनो हैं, वह शायद कभी न होते।

चलिये छोड़िये। किसकी गुनहगारी, कौन कातिल कौन शिकार? मीडिया की मंडी में यह रोज होता है। फिर बिचारे और निरीह राजदीप और आशुतोष गुप्ता जी के ही सिर ठीकरा क्यों फोड़ा जाये। इनसे पहले भी बहुतों ने ऐसा किया था।

संभव है कि इन दोनो ने भी यही दुख भोगा हो, जब किसी ने अपनी पगार बचाने के लिए इनकी पगार बंद कर दी हो। और इसीलिए भी ये दोनो अनुभवी हो चुके हैं। लिहाजा इनके साथ इनके उस्तादों ने जो सलूक किया होगा, वही सलूक अब ये भी अपने चेलो(वफादारों) के साथ कर रहे होंगे। चलता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मीडिया है..यहां सब एक से बढ़कर एक मिल जायेंगे...अपनी–अपनी ढपली अपना–अपना राग भौंकते।

इतना जरुर कहने का मन है...कि अगर वाकई चैनल घाटे में है। इसीलिए परमवंदनीय आशुतोष गुप्ता और राजदीप सरदेसाई ने मोटी पगार वालों (एक लाख से ऊपर, जैसा मीडिया में चंडूखाने की खबरें आ रही हैं...मैं भी उसी चंडूखाने का हिस्सा हूं..भड़ैती के लिए नहीं पेट पालने के लिए) को निपटाकर घाटा कम करके मालिक को खुश करने की कोशिश की है तो पहले इन्हीं दोनो को नौकरी से इस्तीफा देना चाहिए...अगर वाकई जरा भी इनमें गैरत है। वैसे मुझे लगता नहीं....कि इनमें से कोई ऐसा होगा...जैसे मैं सोच रहा हूं..क्योंकि दोनो में से अगर कोई इस काबिल होता तो...अपनी पगार सबसे मोटी बताकर, यह बाकी तमामों के पेट पर लात मारने से पहले खुद अपने ही परिवार और पगार को लात मार सकते थे।।। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा बनने के लिए चाहिए ईमान....जिसकी कल्पना तो मैं खुद से भी नहीं करता हूं..कि 23 साल मीडिया की मंडी में फुटबाल बनने के बाद अब मेरा भी कुछ अपना बाकी बचा रहा होगा.....सादर समर्पित....

Crimes Warrior

Leading public figures urge Parliament to kick criminals out of politics

Hard-hitting press ad and eminent voices call to support Supreme Court ruling

Today senior politicians and former senior officials came out backing the Avaaz campaign denouncing attempts by parliamentarians to overturn a Supreme Court ruling and allow criminal politicians to stay in office if convicted of serious crimes. The Court will today hear a petition from MPs to overturn its ruling.

This comes as a hard hitting full page ad by Indian cartoonist Satish Acharya will be published by Avaaz in The Indian Express on Thursday ahead of an expected Parliamentary vote. The ad, showing MPs clubbing a judge, has been filed on behalf of over 65,000 Indian citizens who backed the Avaaz campaign demanding that politicians accept the Supreme Court ruling to cast out convicted criminals from politics. The advert can be seen here, and the petition here.

Several senior public figures have spoken out backing the campaign including a former Chief of the Election Commission and Chief of Police together with 3 leading Parliamentarians.

T S Krishnamurthy, former Chief of the Election Commission, said:

"Politicians are shamefully fighting to evade responsibility for their actions and protect their powers and privileges. They are abusing their position and bringing politics into further disrepute."

Prakash Singh, former Chief of Police, said:

"Law breakers cannot be law makers. Those convicted must be debarred from parliament. People would like to see them in Tihar."

Politicians are supposed to be the guardians of our democracy, and several have spoken out.

Jay Panda, Lok Sabha MP from the Biju Janata Dal (BJD) party, said:

"Sitting MPs and MLAs ought not to be given benefits which are not available to the average citizen. This defies the equality enshrined in Article 14 of the Indian Constitution. I stand by the Supreme Court ruling that disqualifies MPs and MLAs convicted of serious offences."

Dinesh Trivedi, Rajya Sabha MP, from the All India Trinamool Congress (AITMC) party, said:

"The criminalisation of politics has corroded our great Indian democracy, which came out very clearly in the Vohra Committee report. The common man is fast losing faith in the political system. The recent Supreme Court judgement on the subject is timely and all the political parties should have a serious debate and amend election laws appropriately."

Rajeev Chandrasekhar, Rajya Sabha independent MP, said:

"I welcome the long overdue verdict from Supreme Court disqualifying MPs on date of conviction! Politicians who have been convicted of criminal offences have no place in Parliament."

India has some of the most notorious MPs in the world with nearly 1 in 3 Lok Sabha MPs facing criminal charges.

In the 2009 general elections, there were 275 serious criminal cases pending against 76 of the people elected to the Lok Sabha.

Overall, about 30% of Lok Sabha members and 17% of Rajya Sabha members have criminal cases pending against them, with charges including rape, kidnapping and murder.

For example, Bikram Singh Brahma MP (Congress) was charged with raping a woman. MLAs also face very serious cases, such as Becharam Manna (Trinamool) in West Bengal who is accused in 22 cases, including attempted murder.

Alex Wilks, Campaign Director for Avaaz, said:

"For years, Indians have put up with self serving criminals standing as Parliamentarians but today 65,000 people are shouting enough."

In July the Supreme Court ruled that politicians convicted of serious crimes must lose their seats immediately. Since then, parliamentarians have been trying overturn the ruling by introducing a bill to amend the law the Supreme Court ruled unconstitutional, as well as by submitting a petition for the Supreme Court to review its ruling. The Supreme court is due to decide today whether to review its decision in response to this petition from MPs. The bill is set to be discussed in Parliament this week.

Sushil Kumar Pandeyy
9958561832, 9213796552

MONEY MANAGERS
CONSULTANT- TAX MATTER, RETAIL ASSETS, WORKING CAPITAL

PAN CARD, ITR, BOOK, KEEPING, SALES TAX, PF, ESI, FACTORY ACT.

CMA Data, Cash Credit/Over Draft/WCDL/LAP. PL, DOD Limit, Housing Loan, Vehicle Loan insurance & Investment solution

Office:- A-115, Vakil Chamber, Top Floor, Shakarpur Delhi-92
Resi- D-17, Ganesh puri, Sahibabad, Ghaziabad (U.P.)

क्यों आता है गुस्सा?

गुस्सा भी भावना का एक प्रकार है। लेकिन जब यह भावना व्यवहार और आदत में बदल जाती है, तो आप के साथ–साथ दूसरों पर इसका गंभीर असर पड़ने लगता है। इसके लिए जरूरी यह है कि अपने गुस्से की सही वजह को पहचाना जाए और उन पर नियंत्रण रखा जाए। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है, जो चिड़चिड़ाहट, निराशा और मनमाफिक काम न होने की स्थितियों में सामने आता है। किसी हल्की झुंझलाहट से लेकर किसी स्थिति पर होने आने वाले तेज रिएक्शन को गुस्से के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। चूंकि यह एक नेचुरल इमोशन है इसलिए इससे पूरी तरह निजात पाना संभव नहीं है। गुस्सा आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर इसकी वजह से कोई शख्स खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने लगे, तो इसके नुकसान से बचने के लिए इसे काबू में करना बेहतर है।

गुस्से की मैकेनिजम– जब किसी शख्स को गुस्सा आने वाला होता है, तो उसके हाथ–पैरों में खून का बहाव तेज हो जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, एड्रनिलिन हार्मोन तेजी से रिलीज होता है और बॉडी को इस बात के लिए तैयार कर देता है कि वह कोई ताकत से भरा एक्शन ले। इसके बाद गुस्सा व्यक्ति को धीरे–धीरे अपनी गिरफ्त में लेने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में कुछ और केमिकल रिलीज होते हैं, जो कुछ पलों के लिए बॉडी को एनर्जी से भर देते हैं। दूसरी तरफ नर्वस सिस्टम में कॉर्टिसोल समेत कुछ और केमिकल निकलते हैं। ये केमिकल शरीर और दिमाग को कुछ पलों के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। ये दिमाग को उत्तेजित अवस्था में रखते हैं, जिससे दिमाग में विचारों का प्रवाह बेचौनी के साथ और बेहद तेज स्पीड से होने लगता है।

आंकड़ों के मुताबिक 2010 में 37 फीसदी हत्याओं के मामलों में लोग ऐसे ही चंद क्षणों के गुस्से का शिकार हो गए।

जबकि 2009 में अचानक भड़के गुस्से से मरने वालों की संख्या 35 थी। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि देश में लोगों का पारा बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। हर साल 30 से 32 फीसदी हत्याएं अचानक भड़के गुस्से का नतीजा होती हैं। अगर गुस्से को विज्ञान की नजर से देखें तो किसी व्यक्ति के खुश रहने या नाराज होने की स्थिति के लिए उसके दिमाग में मौजूद सेरोटोनिन का स्तर जिम्मेदार होता है। लंबे समय तक अगर कोई तनाव में रहता है, खुश रहने की उसे वजह ढूंढे नहीं मिलतीं तो ऐसे लोगों के दिमाग में सेरोटोनिन का स्तर 50 फीसदी तक घट जाता है यानी कुदरती तौर पर एक सामान्य इंसान के दिमाग में सेरोटोनिन का जो स्तर मौजूद रहना चाहिए, उससे यह 50 फीसदी कम हो जाता है।

तुरंत गुस्से का अधिक स्तर आमतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, जो सामान्य स्थिति में खुश नहीं रहते, जिन्हें खुश रहने की आदत नहीं होती, जिनमें खुश रहने की प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे लोग गुस्सा होने के लिए बस बहाने की तलाश में रहते हैं। जरा–सी बात कोई उन्हें मिली नहीं कि दहक उठते हैं। दरअसल जो लोग ज्यादा समय तक तनाव में रहते हैं या जिन लोगों की जिंदगी में खुश रहने के अवसर कम होते हैं, ऐसे लोगों की मस्तिष्क की कोशकिाएं गुस्से के लिए अनुकूल स्थिति में ढली होती हैं। ये जरा–सी बात पर इतनी जल्दी और इतने बड़े स्तर पर सक्रिय हो जाती हैं कि सामान्य व्यक्ति अंदाजा ही नहीं लगा पाता कि आखिर सामने वाले को इस तरह गुस्सा क्यों आ रहा है? जब गुस्से का नशा दिलोदिमाग पर हावी हो जाता है तो आदमी वहशी दरिंदा हो जाता है। उस पल वह चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं सोच पाता, जिसमें तर्क हो, जो सकारात्मक बात हो। वह उस समय परिणाम की कतई परवाह नहीं करता। गुस्से की किसी भी हद को पार कर जाना चाहता है।

तनाव की पराकाष्ठा– सवाल है, इसका कारण क्या है? आखिर हम इस कदर क्यों उबल रहे हैं? इस तमाम गुस्से का कारण है हमारी लाइफस्टाइल में बढ़ती व्यस्तता, तनाव, निराशा, उम्मीदों से कम होती सफलता की दर और क्षमताओं से कहीं ज्यादा तय किए गए टारगेट। ये सब मिलकर हमें तोड़ रहे हैं। शहरी लोग दिन–ब–दिन तनाव की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ रहे हैं। उस पर सड़कों पर लगने वाला जाम और मौसम की अनियमितता आग में घी का काम करती है। लोग उबल पड़ते हैं। जरा–सी बात में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। हर गुजरते साल रोष में होश खोने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यह इजाफा बताता है कि किस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे कामकाज हावी हो गए हैं।

साइड इफेक्ट्स–

बॉडी में एड्रिनलिन और नोराड्रिनलिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है।

हाई ब्लड प्रेशर, सीने में दर्द, तेज सिर दर्द, माइग्रेन, एसिडिटी जैसी कई शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं।

जो लोग जल्दी–जल्दी और छोटी–छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें स्ट्रोक, किडनी फेल्योर और मोटापा होने के चांस रहते हैं।

ऐसा माना जाता है कि गुस्से में व्यक्ति ज्यादा खाता है, जिसका रिजल्ट होता है मोटापा।

ज्यादा पसीना आना, अल्सर और अपच जैसी शिकायतें भी गुस्से की वजह से हो सकती हैं।

ज्यादा गुस्से की वजह से दिल की ब्लड को पंप करने की क्षमता में कमी आती है और इसकी वजह से हार्ट मसल्स डैमेज होने लगती हैं। इससे हार्ट अटैक होने की आशंका बढ़ जाती है।

लगातार गुस्से से रैशेज, मुंहासे जैसी स्किन से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं।

भारत की मेजबानी करने को तैयार है न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बीसीसीआई की छोटे से छोटे दौरे की मांग को स्वीकार करते हुए अगले साल जनवरी फरवरी में भारत के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के संक्षिप्त कार्यक्रम की सोमवार को यहां घोषणा की।

भारत 19 जनवरी से 18 फरवरी के बीच न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच और उसके बाद दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेगा। इससे पहले इस दौरे में तीन टेस्ट, पांच वनडे और एक टी20 मैच शामिल था। लेकिन रिपोर्टों के अनुसार भारतीय बोर्ड न्यूजीलैंड के संक्षिप्त दौरे के पक्ष में था ताकि उनकी टीम फरवरी में होने वाले एशिया कप में भाग ले सके। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड वाइट ने कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत उनकी टीम के खिलाफ पांच एकदिवसीय मैच खेलेगा। वाइट ने बयान में कहा कि यह अच्छा है कि ब्लैक कैप्स (न्यूजीलैंड) दुनिया की चोटी की वनडे टीम के खिलाफ पांच एकदिवसीय मैच खेलेगी। उन्होंने बताया कि भारत दौरे के मैच स्थलों की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी। भारत अपने एकदिवसीय अभियान की शुरूआत 19 जनवरी को वनडे मैच से करेगा। इसके बाद 22, 25, 28 और 31 जनवरी को वनडे मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच सात से 11 फरवरी और दूसरा मैच 14 से 18 फरवरी के बीच खेला जाएगा।

AAFT
PIONEER IN MEDIA EDUCATION
21ST YEAR IN EDUCATION
CAMPUS 2 Lac Sq.Ft.
STUDENTS FROM 92 COUNTRIES
10,000 ALUMNI

Learn From The
Media Industry Leaders

Workshops & Seminars by

Anil Kapoor
Actor

Satish Kaushik
Director / Actor

Karl Bardosh
Professor, Tisch School of Arts, NYU

Manoj Pahwa
Film/TV Actor

Short Term Courses

3 MONTH
- Production Direction & TV Journalism
- Video Editing & Sound Recording
- Camera & Lighting Techniques
- Acting & Presentation
- TV Graphics & Animation
- Still Photography & Journalism
- Sound Recording & Radio Production
- Mass Media Research & Planning
- Screenplay Writing
- Print and Advertising Graphics
- 2D Graphics and Animation
- Virtual Set Design (3DS Max)
- 3D Graphics & Animation (MAYA)
- Compositing and Special Effects
- Internet & Web Design

1 YEAR
- Diploma in Camera & Lighting Techniques
- Diploma in Post Production
- Diploma in Acting for Film & TV
- Diploma in Visual Communication
- Diploma in Multimedia
- Diploma in 3D Animation & VFX
- Diploma in 3D Animation Film Making
- PGD in Media & Entertainment
- PGD in TV Journalism & Communication
- PGD in Film & TV Production
- PGD in Still Photography & Photo Journalism
- PGD in Advertising & Brand Communciation
- PGD in Public Relations & Events

Marwah Studios Complex, FC-14/15, Film City, Sector-16A, NOIDA, Delhi (NCR), India
Toll Free: 1800-102-6066 | Mob: 08527146124, 08586978524
Ph: 0120-4831100 | sms AAFT to 57575
www.aaft.com | help@aaft.com
ASMS | ASC | uclan

Publishing on 10th of every month
RNI No. 62500/95
REGD. No. DL (E)-01/5149/2012-2014
LICENCE TO POST WITHOUT
PRE-PAYMENT No. U(C)223/12-14

To,

If undelivered, Please return to:
न्यूज़ पेपर्स एसोसिएशन
ऑफ इण्डिया
POST BOX 9235, NEW DELHI-110 092

यदि आप लेख, रचना, समाचार, विचार प्रेषित करना चाहते हैं तो आप अपने अप्रकाशित लेख निम्न पते पर भेजें।

आपको ***NAI*** का यह अंक कैसा लगा, इस बारे में अपने सुझाव हमें निम्न पते पर भेजें।

एन. ए. आई.
A-115, Vakil Chambers, Top Floor,
Shakarpur, Delhi-110092, Ph.: 011-22058133

Editorial Board

Founder	Late Dr. M. R. Gaur
Editor Publisher-Printer	Vipin Gaur
Counsultant Editor:	Dr. Smita Mishra
Managing Editor:	Dilip Kumar
	K. R. Arun
Legal Advisors:	Nikhat Anjum Malik
Advocate Delhi Highcourt	Rajesh Sharma
	Adv. P. Yadav
Office Secretary	Pawan Pant

- Bureau Chief -

Guwahati:	Runu Hazarika
Mumbai:	Mr. Dinesh K. Mishra
Bangalore:	Mr. M.K. Jain
Jaipur :	Mr. Bhanwar Singh Ranawat
Chennai:	Mr. P.C.R. Suresh
M.P. & C.G.	Mr. O. P. Jain
Kerela	Mr. Suvarna Kumar
Goa	Dr. Vivek Gaitonde

DPMI honors media on its 18th Foundation Day Celebrations

Delhi Paramedical & Management Institute (DPMI) celebrated 18 years of its existence in the arena of Paramedical Science Education by honoring and appreciating media persons who valiantly risked their lives in giving extensive coverage to the Uttarakhand Floods in June 2013. Ms. Sheila Dikshit, Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi gave away the tokens of appreciation to these media persons. This ceremony was held at Hindi Bhavan, New Delhi.

Apart from imparting quality education, DPMI has always strived to do its bit in putting in service to the society, be it organizing "Kavad Shivirs" or lauding efforts of those who do something for the country. Honouring the media persons, who braved the ravages of nature and brought us news of our near and dear ones, who were stranded in Uttarakhand during the flood

in June 2013, is one such initiative of DPMI.

The Hon'ble Chief Minister was most delighted in handing over these tokens of appreciation to journalists from various media like NDTV, TV100, Amar Ujala, Sahara TV, Dainik Jagran, ETV and UNI among others. Prominent journalists who were honoured included Mr. Sushil Bahuguna, Producer NDTV, Mr. Hridesh Joshi, NDTV, Mr. Manjit Negi from India News and Mr. Ved Vyas Uniyal from Amar Ujala among others.

She said on the occasion, "Delhi Government is putting its best foot forward in helping the Uttarakhand Government in all relief operations and supporting it either monetarily or in "kind" in order that the people there find a firm foothold for themselves all over again. I applaud the efforts of all Journalists who showed courage in giving extensive coverage to the devastation and bringing news of the stranded pilgrims to their family back home."

The students of DPMI showcased two skits during the event. The first one was on female feticide. The second skit told the tale of Aruna Shanbaug, the nurse of Kings Edward Memorial Hospital, Mumbai, who was brutally sodomised and left to die by a ward boy of the same hospital in 1973. She has been in a vegetative state since then. The skit by DPMIstudents portrayed the stupendous efforts of the nurses of Kings Edward Memorial Hospital, who have selflessly taken care of Aruna for the past 40 years so much so that they had fought all odds to win a legal battle against euthanasia for Aruna. Also present on the occasion were stalwart Social Activists Mr. Diwan Singh Nayal and Mr. Hira Singh Rana, who lit the ceremonial lamp along with Mr. Arun Juneja, Patron DPMI, Mr. Diwan Singh Bajeli, Sr. Journalist from The Hindu Newspaper, Dr. Ramesh Kandpal, Mr. Vinod Bachheti, Chairman DPMI and Dr. R S Gupta, Director AcademicsDPMI.

Printed, Published by Vipin Gaur on behalf of News papers Association of India, Printed at Mayank Offset Process 794/95 Guru Ramdas Nagar Ext. Laxmi Nagar Delhi-92 and Published from J-51, DLF Dilshad Delhi-95, Editor: Gayatri Gaur. All disputes settled in Delhi Court only.